RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 29 APRIL TO 05 MAY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 36 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कच्चा तेल वायदा में 'लेने के देने' पड़ने की घटना के बाद एमसीएक्स ने मार्जिन 125% तक की

Page 2

SBI सिर्फ 45 मिनट में फटाफट दे रहा है सबसे सस्ता लोन

Page 4

FMCG कंपनियों ने पकड़ा कन्ज्यूमर के घर का सीधा रास्ता

Page 5

editoria!

बिना टैक्स का राजकाज

लॉकडाउन के दिन बीतने के साथ अब धीरे-धीरे यह साफ होता जा रहा है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को कितना नुकसान पहुंचा है और इससे किस तरह की चुनौतियां पैदा हुई हैं। हाल तक सबको कुछ अंदाजा तो था कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था लहूलुहान हो जाएगी, लेकिन कितने मोर्चों पर किस तरह के नुकसान सामने आ सकते हैं, यह अब पता चल रहा है। सबसे पहली मार सरकारी खजाने पर पड़ी है। राज्य सरकारों के हाथ खाली हो गए हैं और टैक्स वसूली लगभग ठप है। पिछले दिनों केरल सरकार ने साफ कहा कि उसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हैं। राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि 'अप्रैल में राज्य सरकार मात्र 250 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। केंद्र से जीएसटी में राज्य का हिस्सा मिल जाए तो हम 2,000 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को छूने में सक्षम होंगे। लेकिन वेतन के भुगतान के लिए हमें 2,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो फिर भी पूरे नहीं पड़ेंगे।'अन्य कई राज्यों का भी यही हाल है। रिसर्च फर्म इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ा तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत पतली हो सकती है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के अपने स्रोतों से आने वाले राजस्व की आमद न के बराबर हो गई है। इसलिए कई राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी है। इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि केंद्र सरकार को भारी रकम जुटानी होगी और इसका बड़ा हिस्सा राज्यों को खर्च के लिए देना होगा। सरकार की मुश्किल यह भी है कि लोगों ने पीएफ से पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल के शुरुआती 11 दिनों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ईपीएफओ के पास 3 महीने की सैलरी निकालने का आवेदन डाला है। दरअसल लोगों में असुरक्षा और अनिश्चितता का भाव घर कर गया है। उन्हें भय है कि सारा सिस्टम बैठ गया तो उनके पैसे डूब जाएंगे। इसी डर और आशंका ने कैपिटल मार्केट का भी बुरा हाल कर रखा है और इसका असर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। जाने- माने म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलटन इंडिया ने घाटे के चलते अब अपने 6 डेट फंड बंद कर दिए हैं जिससे निवेशकों के करीब 28 हजार करोड़ रुपए अटक गए हैं। कंपनी का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाला है, जिससे उसके सामने नकदी का संकट पैदा हो गया है। बिकवाली का दबाव बढ़ने से अब इन सभी फंड्स की सिक्युरिटीज सस्ते में बेचनी पड़ेंगी। कंपनी का कहना है कि निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन कई चरणों में। कोरोना संकट के चलते दूसरे म्यूचुअल फंड्स पर भी दबाव बढ़ेगा। डेट फंड्स में नकदी का संकट बढ़ सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए बाजार से कर्ज उठाना मुश्किल रहेगा। केंद्र सरकार को इन सब पहलुओं का ध्यान रखते हुए आगे के कदम उठाने होंगे।

लॉकडाउन के बीच 21 हजार रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए

सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Lockdown) को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार (Government of India) ने ईएसआई योजना (ESIC Scheme) का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हों। इससे पहले साल 2016 तक मासिक आय की सीमा 15 हजार रुपए थी, जिसे 1 जनवरी, 2017 से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया गया था।

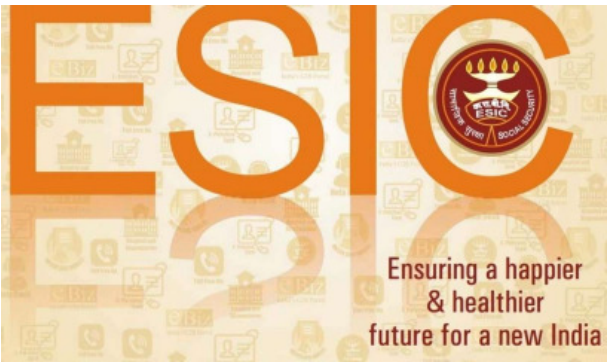

लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से की गई 5 बड़ी घोषणाएं

मिलती रहेंगी सभी सुविधाएं

ESIC ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी।

एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल

कर्मचारी अपने मेडिकल कार्ड, जिसके जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती हैं वो एक्सपायर हो गया है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो अपने पुराने कार्ड पर ही सभी सेवाएं पा सकते है। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है।

प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स से ली जा सकती हैं दवाएं

ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की भी सुविधा प्रदान की है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद बाद में ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम कर सकेंगे। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वो अस्पताल नहीं जा पा रहे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

अन्य अस्तापतालों में हो सकता है इलाज

जिन ESIC अस्पतालों को COVID-19 अस्पताल में बदल दिया है वहां इलाज कराने जाने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर पर इन अस्पताल में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESIC ने कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा।

कंपनियों को मिली बड़ी राहत

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देशभर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सोशल सिक्योरिटी स्कीम (Social security scheme) से फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर्स जुड़े हैं। इससे पहले जनवरी में ईएसआईसी में 12.19 लाख नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए थे।

मूडीज ने 2020 में भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% किया

नई दिल्ली। एजेंसी

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दिया, जबकि मार्च में उसने इसके 2.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई थी। मूडीज को उम्मीद है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रह सकती है। मूडीज ने 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 (अप्रैल 2020 में अद्यतन)' में 2020 के दौरान जी20 देशों की वृद्धि दर के अनुमानों में 5.8 प्रतिशत की कमी की। मूडीज ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के बंद होने की आर्थिक लागत तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि जी20 देशों की वृद्धि दर में सामूहिक रूप से 5.8 प्रतिशत की कमी होगी। यहां तक कि सुधार के बाद भी ज्यादातर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कोरोना वायरस महामारी से पहले वाले स्तर के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020 में चीन की वृद्धि दर एक प्रतिशत रह सकती है। मूडीज ने कहा, 'भारत ने देशव्यापी लॉकडाउन को 21 दिनों से बढ़ाकर 40 दिनों तक कर दिया, लेकिन अप्रैल के अंत में कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधों में छूट दी है। देश ने यह सुनिश्चित किया कि उसके कई हिस्से वायरस से मुक्त रहें। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई है।'

कोविड-19 की वजह से मार्च में कच्चा इस्पात उत्पादन घटकर 7$.8 लाख टन

नयी दिल्ली। भारत का मार्च माह का कच्चा इस्पात उत्पादन,इससक पिछले महीने की तुलना में 23 प्रतिशत घटकर 73.8 लाख टन रह गया जबकि कोविड-19 के प्रकोप और उसकी वजह से लॉकडाऊन' के कारण निर्यात और आयात भी प्रभावित हुआ। इस्पात मंत्रालय ने कहा कि कोरोनोवायरस के फैलने का असर देश में इस्पात की खपत पर भी पड़ा है, जो माह दर माह मार्च में 6.6 फीसदी घटकर 5.80 लाख टन रह गई । इस वर्ष फरवरी में कच्चा इस्पात उत्पादन 95.6 लाख टन था। उसके मुकबाले यह मार्च में 22.7 प्रतिशत घट कर 73.8 लाख टन रहा। इसी दौरान तैयार इस्पात का निर्यात 20.5 प्रतिशत घट कर 4.53 लाख टन और आयात 26.9 प्रतिशत गिर कर 2.93 लाख टन रहा।

शेयर बाजार में बहार

605 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी 9500 के पार बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजार बुधवार को भी हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स दिन के अपने उच्च स्तर 32897.59 पर पहुंचने के बाद 32720 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1.89 फीसद की तेजी या अंकों की उछाल के साथ बुधवार को कारोबार समाप्त किया। वहीं निफ्टी भी आज 9408 के स्तर पर खुला और दिन के सबसे उच्च स्तर 9,599.85 तक पहुंचा। अंत में 9500 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी आज 172.45 अंकों की बढ़त के बाद 9,553.35 के स्तर पर बंद हुआ। जहां तक सेक्टोरियल इंडेक्स की बात है तो निफ्टी मिडकैप-50, ऑटो, बैंक, आईटी, मीडिया, मेटल, पीयूसी बैंक, प्राइवेट बैंक फायदे में रहे तो वहीं फार्मा और एफएमसीजी नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में जबरदस्त तेजी है। आज के कारोबार में अब तक 9599.85 के उच्च शिखर पर पहुंच कर निफ्टी फिलहाल 191 अंकों की बढ़त के साथ 9572 के स्तर पर है तो वहीं सेंसेक्स 625.27 अंकों की उछाल के साथ 32,739.79 के स्तर पर।

एक्सिस बैंक के शेयरों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, कंपनी ने 2019-20 के मार्च तिमाही के लिए 1,387.78 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया। लेकिन ब्याज आय में 19 फीसदी तो लोन ग्रोथ में 15 फीसदी का उछाल आया है। बैंक ने कोरोना संकट के लिए 3,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। बाद में इसके स्टॉक में सुधार देखा जा रहा है और बीएसई पर यह 2.38 फीसद के नुकसान के साथ 444.70 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

ब्रोकरों के अनुसार शंघाई, हांगकांग और सियोल जैसे प्रमुख एशियाई बाजारों के सकारात्मक रुख का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। निवेशकों को अमेरिका के फेडरल रिजर्व की मौद्रित नीति का इंतजार भी है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर धीरे-धीरे लॉकडाउन (बंद) खत्म होने की उम्मीद से भी निवेशकों की धारणा मजबूत दिख रही है। बंद खत्म होने से आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। आरंभिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को 122.15 करोड़ रुपये की बिकवाली की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट कच्चा तेल भाव 3.52 प्रतिशत बढ़कर 23.54 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है।

रुपया 52 पैसे मजबूत होकर 75.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर के नरम पड़ने तथा घरेलू शेयर बाजारों के बढ़त में रहने से बुधवार को अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 52 पैसे मजबूत होकर 75.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यह लगातार तीसरा दिन है जब रुपया मजबूत हुआ है। इस दौरान रुपया 80 पैसे मजबूत हुआ है। कारोबार की शुरुआत में भारतीय मुद्रा 75.94 रुपये प्रति डॉलर पर खुली। कारोबार के दौरान इसने 75.60 रुपये प्रति डॉलर का उच्चतम और 75.96 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर को छुआ। अंत में यह 52 पैसे बढ़कर 75.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एक दिन पहले मंगलवार को यह 76.18 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। कारोबारियों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजारों की बढ़त के साथ शुरुआत ने रुपये की मदद की। कई देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त करने की शुरुआत से बाजार धारणा में सुधार हो रहा है। इस बीच बीएसई का सेंसेक्स 519.56 अंक की बढ़त के साथ 32,634.08 अंक पर और निफ्टी 150.70 अंक की तेजी के साथ 9,531.60 अंक पर चल रहा था। कच्चे तेल का ब्रेंट वायदा 1.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 20.86 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

वित्तीय परिदृश्य बिगड़ने पर दबाव में आ सकती है भारत की रेटिंगः फिच

नयी दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा है कि यदि कमजोर वृद्धि अथवा वित्तीय मानदंडों में ढील से भारत के वित्तीय परिदृश्य की स्थिति बिगड़ती है तो भारत की सावरिन रेटिंग दबाव में आ सकती है। फिच ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिये भारत सरकार वित्तीय क्षेत्र में नये प्रोत्साहन उपायों की घोषणा कर सकती है। ऐसी स्थिति में उसकी भारत की रेटिंग का आकलन संकट बाद के परिवेश और उस दौरान अपनाई जाने वाली संभावित मध्यमकालिक वित्तीय कार्ययोजना के आधार पर किया जायेगा। फिच ने एक वक्तव्य में कहा है, "भारत की वृद्धि दर कम रहने अथवा नये वित्तीय प्रोत्साहनों से यदि वित्तीय परिदृश्य में स्थिति बिगड़ती है तो सावरिन रेटिंग पर दबाव बढ़ सकता है। इस मामले में यह गौर करने वाली बात है कि जब इस संकट की शुरुआत हुई थी तब भी भारत के सामने वित्तीय क्षेत्र में सीमित गुंजाइश ही थी।" रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि महामारी के नियंत्रण में आने के बाद सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों को फिर से कड़ा कर सकती है लेकिन भारत का रिकार्ड इस मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने और नियमों को कड़ाई से पालन के मामले में भारत का रिकार्ड हाल के वर्षों में मिला जुला रहा है। आने वाले समय में इस रिकार्ड का भी हमारे आकलन पर प्रभाव दिखाई देगा। फिच ने दिसंबर 2019 में भारत की रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ 'बीबीबी-(नकारात्मक) पर बनाये रखा था। रेटिंग एजेंसी ने भारत की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी काफी घटाकर 0.8 प्रतिशत कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण पर होने वाले खर्च और सरकारी स्तर पर इस पर काबू पाने के लिये किये जा रहे प्रयासों को देखते हुये आर्थिक वृद्धि के अनुमान में यह कमी की गई है। इससे पहले एजेंसी ने 2020- 21 के लिये 5.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था।

आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही की छूट होः गडकरी ने राज्यों ने कहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों से अपील की कि वे इस समय कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों के बीच आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने तथा उन्हें जारी किए गए 25,000 करोड़ रुपये उपयोग करने के लिए कहा। राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में गडकरी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, ताकि परियोजनाएं लालफीताशाही का शिकार न बन सके। गडकरी ने कहा कि परिवहन के जुड़े मसलों का समाधान करने के लिए उनका मंत्रालय एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। गडकरी ने बताया कि वह अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को वर्तमान स्थिति से दो से तीन गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह भी मौजूद थे।

कच्चा तेल वायदा में 'लेने के देने' पड़ने की घटना के बाद एमसीएक्स ने मार्जिन 125% तक की

मुंबई। ऑनलाइन वायदा बाजार मंच एमसीएक्स ने पिछले दिनों कच्चे तेल के वायदा कारोबार में भाव शून्य से भी बहुत नीचे चले जाने की घटना के मद्देनजर अपने यहां भविष्य की डिलिवरी के अनुबंधों पर मार्जिन मनी 125 प्रतिशत तक कर दी है।यह निर्णय बृहस्पतिवार से प्रभावी हो जाएगा और प्रति लॉट 1,95,000 रुपये तक मार्जिन रखनी होगी। एमसीएक्स ने बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा है कि वह जोखिम प्रबंध के लिए 30 अप्रैल से अतिरिक्त उपाय करने जा रहा है।देश में कच्चा तेल वायदा कारोबार का 95 प्रतिशत कारोबार एमसीएक्स के माध्यम से होता है। उसने कारोबार में बहुत सावधानी बरतने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत अनुबंधों के लिए प्रस्ताव रखने वालों को जोखिम के आधार पर 95,000 रुपये से 1,95,000 रुपये प्रति लॉट का मार्जिन शुरू में ही रखना होगा। अभी तक पिछले दिन के बाजार भाव में नुकसान के हिसाब से मार्जिन तय होता था।यह मौजूदा दर से बहुत ऊंची है। मार्च के शुरू में इस बाजार में मार्जिन 12.75 प्रतिशत था जो 16 मार्च को बढ़ कर 57.9 प्रतिशत तक पहुंच गया

था।वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में 20 अप्रैल को कीमतों के शून्य से नीचे गिर जाने के बाद एमसीएक्स भी उसके अगले दिन उलझ गया था। एमसीएक्स ने सोमवार को समाप्त होने वाले अनुबंधों के निपटान के लिए एक रुपये प्रति बैरल का अंतरिम भाव तय किया था। उसके इस कदम को कुछ कारोबारियों ने बड़े ब्रोकरों के नुकसान को दूसरों की लागत पर कम करने का एक तरीका बता कर इसकी आलोचना की। आलोचना होने के बाद उसे इन सौदों के निपटान की अंतिम दर प्रति बैरल शून्य से 2,884 रुपये नीचे तय करनी पड़ी।बताया गया कि इस उथल-पुथल में मई के अनुबंधों में इस एक्सचेंज के साथ काम करने वाले ब्रोकरों को चार सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।शून्य से नीचे का अर्थ है कि क्रेता को उल्टे विक्रेता से पैसा मिलेगा।एक्सचेंज ने आगे कहा कि एमसीएक्स में पिछले 15 साल से कच्चे तेल के वायदा अनुबंध में कारोबार किया जा रहा है। इसमें होने वाले अनुबंध को हमेशा ही न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (एनवाईएमईएक्स) के डब्ल्यूटीआई क्रूड आयल के अनुबंध निपटान मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर उसके अनुरूप ही निपटान किया जाता है।

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने राज्य सरकार को समर्थन एवं सहयोग दिया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्य प्रदेश में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों को 75 उत्पाद दान किए

भारत के प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ने मध्य प्रदेश में कोविड-19से लड़ने के लिए आवश्यक उत्पादों का दान किया। वैश्विक महामारी से लड़ने में लोगों की मदद के लिए, ब्रांड ने सरकारी अस्पकतालों को लगभग 75 उत्पाद दान किया है। ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर और एमवाई हॉस्पिटल इंदौर हैं। दान में दिये गये उत्पादों में रेफ्रिजरेटर, वाटर प्यूरीफायर और टीवी शामिल हैं। इस कठिन परिस्थिति में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सभी संभव तरीकों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर रहा है। इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए,यंग लैक किम - एमडी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने कहा कि 'हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार और नागरिकों को अपना पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखनाबेहद जरूरी है। इसलिए हम मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य और स्वच्छता बढ़ाने वाले उत्पाद दान कर रहे हैं, जैसे वाटर प्यूरीफायर, और रेफ्रिजरेटर। इस कठिन समय में हम समाज के लिए सार्थक योगदान देना चाहते हैं। भारत में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में काफी तेज वृद्धि हुई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने का संकल्प लिया है। ब्रांड राज्यों को सहायता प्रदान करेगा तथा लोगों को प्रोत्साहित करने और इसके खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

TDS-GST पेमेंट की डेडलाइंस ने बढ़ाईं मुश्किलें

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन के बीच कंपनियों, अकाउंटेंट्स और सीए के दफ्तर बंद होने से चौथी तिमाही के टीडीएस और मार्च महीने के जीएसटी भुगतान को लेकर ट्रेड-इंडस्ट्री पसोपेश में फंसी नजर आ रही है। 30 अप्रैल से 5 मई के बीच कई डेडलाइंस का सामना कर रहे कारोबारियों और टैक्स प्रफेशनल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इनकी तारीखें बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने ज्यादातर रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले ही 30 जून तक बढ़ा रखी है।

इंडस्ट्री और टैक्स प्रफेशनल्स की ओर से कहा गया है कि बिना ब्याज चौथी तिमाही जनवरी-मार्च और अप्रैल का टीडीएस भरने की डेट 30 अप्रैल है, लेकिन लॉकडाउन के चलते कंप्यूटिंग संभव नहीं है। सीए चिराग चौहान ने बताया कि ज्यादातर कंपनियों और टैक्सपेयर्स के दस्तावेज भी उनके बंद दफ्तरों में रह गए हैं, जबकि एकाउंटेंट्स और दूसरे संसाधन भी ठप हैं। ऐसे में यह समयसीमा कम से कम 31 मई तक बढ़ाई जानी चाहिए।' उन्होंने कहा कि प्रफेशनल टैक्स भी 31 मार्च तक भरा जाना था, जिसे सरकार ने लॉकडाउन के चलते 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब तक कई रिटर्न नहीं भरे जा सकने के चलते इसका भुगतान भी संभव नहीं लगता।

पांच करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए मार्च महीने का जीएसटी भरने की ड्यू डेट 5 मई है, लेकिन यहां भी दफ्तरों की बंदी और वर्किंग कैपिटल की कमी आड़े आ रही है। जीएसटीआर-3बी नहीं भरे जा सकने और कंप्यूटिंग नहीं होने से लोग भुगतान करने की हालत में नहीं हैं। सरकार ने लॉकडाउन के चलते मार्च के जीएसटी भुगतान की डेडलाइन 20 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दी थी।

चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने पीएम को पत्र लिखकर कुछ महीनों के लिए जीएसटी भुगतान टालने की मांग की है। संगठन के मुताबिक जीएसटी इनवॉइस बनते ही लाइबिलिटी बन जाती है, जिसे अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कराना होता है, लेकिन कारोबार बंद होने से किसी के पास कोई पैसा नहीं आया है। इसके अलावा रेंट, ब्याज, किराया और मजदूरों के वेतन का बोझ कायम है। सरकार कम से कम लॉकडाउन की अवधि का टैक्स भुगतान रोकने या ब्याज में रियायत पर विचार करे।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा है कि अगर छोटे कारोबारियों को टैक्स भुगतान टालने की छूट नहीं मिली तो पहले ही नुकसान झेल रहे कारोबारियों का वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा और कोरोना संकट से उबरना मुश्किल होगा।

छोटे और खुदरा व्यापारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना की जाए

इंदौर। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी रत्न विशेषज्ञ ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए भी भविष्य निधि की स्थापना की जानी चाहिए। वाधवानी में जानकारी देते हुए बताया कि खुदरा, मध्यम, छोटे व्यापारी हमेशा से सरकार को राजस्व वसूली करने में सहयोग करते आ रहे हैं। ऐसे में इनको भी 60 वर्ष की उम्र के बाद जीवनयापन के लिए भविष्य निधि की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वृद्धावस्था में इन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझने के लिए शासकीय संभल प्राप्त हो। व्यापारी प्रकोष्ठ के संतोष वाधवानी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से रिटेल, मध्यम, छोटे व्यापारियों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि आजादी के बाद से व्यापारी हमेशा सरकार के लिए सेल्स टैक्स, वैट अब जीएसटी का निशुल्क संग्रह करता आया है। जबकि सरकारी एजेंसी तहसील आदि भी वसूली के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त चार्ज लेती हैं। ऐसे में छोटे और खुदरा व्यापारियों भी अधिकार बनता है कि उन्हें भी 60 वर्ष के बाद जीवनयापन के लिए व्यापारी भविष्य निधि की स्थापना करके लाभान्वित किया जाए।

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चरणबद्ध किये गए कार्य

नागदा। आईपीटी नेटवर्क

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा के इकाई प्रमुख श्री के. सुरेश जी के मार्गदर्शन एवं मानव संसाधन विभाग के उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी की देखरेख में संचालित कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) के तहत ग्रासिम उद्योग द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण के लिए नागदा शहर एवं 25 ग्रामों में जन जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण में उद्योग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण से बचाव के लिए मार्गदर्शन पोस्टरों को लगवाया गया तथा साउंड सिस्टम के माध्यम से जनसामान्य को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार किया गया साथ ही संक्रमण के बचाव की जानकारी के पचे छपवा कर वितरित किये गए । दूसरे चरण में करोना से बचाव के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री आर पी वर्मा के निर्देशानुसार नागदा शहर एवं 25 ग्रामों को सेनीटाइज करने के सिए कैल्सियम हाइपो का छिड़काव किया गया। तृतीय चरण में 25 गांव में ग्रामीण जनों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी प्रदान करते हुए 10000 मास्क का वितरण किया गया साथ ही मास्क के उपयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। चतुर्थ चरण में प्रशासन के अनुसार लॉक -डाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 25 ग्रामों में 600 गरीब परिवारों को राशन एवं आवश्यक सामग्री किट प्रदान की जा रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित सभी ग्रामों की पंचायतों से प्राप्त ग्राम में निवासित परिवारों एवं अत्यंत गरीब परिवारों की सूची के आधार पर यह किट प्रदान की जा रही है ताकि लॉक डाउन से प्रभावित गरीब लोग अपने घरों में रहकर अपना जीवन यापन कर सके।

ADITYA BIRLA
GRASIM

SBI सिर्फ 45 मिनट में फटाफट दे रहा है सबसे सस्ता लोन

6 महीने तक नहीं देना है EMI

नयी दिल्ली। लॉकडाउन में अगर आपको पैसे की सख्त जरूरत है और आपको यह नहीं सूझ रहा है कि आप पैसों का कैसे और कहां से इंतजाम करें, ताकि आपकी तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें, तो आप कतई नहीं घबराएं. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने आम आदमी की इन्हीं जरूरतों को देखते हुए इमरजेंसी लोन पेश किया है। इसके लिए आपको अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही केवल 45 मिनट में एसबीआई से लोन प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते है?

छह महीने तक ईएमआई के झंझट से छुटकारा

सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीआई से इमरजेंसी लोन लेने के बाद आपको शुरुआत के करीब छह महीने तक मासिक किस्त यानी ईएमआई देने की जरूरत नहीं होगी। यानी आप अगर मई के महीने में एसबीआई से इमरजेंसी लोन लेते हैं, तो आपको अक्टूबर तक ईएमआई का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी. आपकी ईएमआई छह महीने के बाद से ही शुरू होगी।

केवल एसबीआई के ग्राहकों को ही मिल सकता है इमरजेंसी लोन

एसबीआई के इमरजेंसी लोन सुविधा उसके अपने ग्राहकों के लिए ही है। इसके तहत अन्य बैंक के ग्राहकों को सस्ता और फटाफट लोन नहीं मिल सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीआई की ओर से अपने ग्राहकों को सबसे सस्ता 10.50 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा, जो फिलहाल देश के किसी भी बैंक के ब्याज से काफी सस्ता है।

ऐसे मिलेगा इमरजेंसी लोन

इमरजेंसी लोन पाने के लिए एसबीआई के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड नंबर से PAPL लिखकर स्पेस छोड़कर अपना एकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक लिखें और फिर उसे 567676 पर मैसेज भेज दें। आपके द्वारा यह मैसेज भेजने के बाद आपके पास पलटकर मैसेज आएगा कि आप इमरजेंसी लोन पाने के पात्र हैं या नहीं। अगर आपके पास पलटकर मैसेज आ गया और आपको इसके लिए योग्य बताया गया, तो आपको चार प्रोसेस फॉलो करने के बाद लोन मिल जाएगा। इसके बाद एसबीआई के एप में अवेल नाऊ (Avail Now) पर क्लिक करें, फिर इसके बाद समयावधि और रकम चुनें। इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे डालते ही पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा।

लॉकडाउन के दौरान बढ़ते जोखिम पर बैंक घटा रहे क्रेडिट कार्ड लिमिट

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन में नकदी संकट को देखते हुए एक्सिस, आईसीआईसीआई व कोटक महिंद्रा सहित कई बैंकों ने ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट 80% तक घटा दी है। एक्सिस बैंक ने दो लाख ग्राहकों की क्रेडिट लिमिट में कटौती की है। पैसाबाजार डॉट कॉम के सह-संस्थापक एवं सीईओ नवीन कुकरेजा ने कहा कि बैंकों को लगता है कि कोविड-19 संकट के कारण बने हालात में कुछ क्रेडिट कार्डधारक वित्तीय दबाव में आ सकते हैं, जिससे उनके भुगतान पर जोखिम आ सकता है। हालांकि, कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष (कस्टमर एसेट्स) अंबुज चंदना ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। क्रेडिट कार्डधारकों की कर्ज पाने की योग्यता व कार्ड से खर्च के विश्लेषण पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटाई या बढ़ाई जाती है।

तीन कारण...जिससे बैंक घटा रहे लिमिट

मोरिटोरियम लेने पर: जो ग्राहक आरबीआई से मिली तीन महीने की राहत का फायदा उठा रहे हैं, बैंक उनकी क्रेडिट कार्ड लिमिट घटा रहे हैं। बैंकों का मानना है कि जो ग्राहक सुविधा ले रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में ग्राहक वित्तीय जरूरतें पूरी करने को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और नकदी संकट के कारण भुगतान में देरी होगी।

क्रेडिट कार्ड के कम इस्तेमाल पर: क्रेडिट कार्ड के कम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की लिमिट में भी कटौती हो रही है। कई ग्राहक ऐसे हैं, जिनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दो लाख है और उन्होंने 12-24 महीने में महज 10 हजार से 20 हजार रुपये ही खर्च किए हैं। इन ग्राहकों की भी क्रेडिट कार्ड लिमिट घटाई जा सकती है।

भुगतान में देरी या डिफॉल्ट पर: क्रेडिट कार्ड रखने वाले 25-35 फीसदी ग्राहक बकाया भुगतान में देरी करते हैं या कभी न कभी डिफॉल्ट किया है। बैंकों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड से खर्च और भुगतान के हिसाब से लिमिट तय की जाती है। ऐसे में पैसा चुकाने में देरी या डिफॉल्ट करने वाले जिन ग्राहकों के भुगतान पर जोखिम की आशंका रहती है, उनकी क्रेडिट लिमिट घटा दी जाती है।

बैंक उन ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं, जो कुछ महीनों से 50% से ज्यादा राशि खर्च करने के साथ समय पर भुगतान करते रहे हैं। मान लीजिए, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक लाख रुपये है। उसमें से आपने 60,000 खर्च किए हैं और समय पर उसका भुगतान भी कर दिया है। ऐसे ग्राहकों पर बैंकों का भरोसा बना है। उन्हें लगता है कि आगे भी ये खर्च करते रहेंगे और बकाया पर जोखिम नहीं होगा। बैंक ऐसे ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं।

कोरोना से जंग में ADB ने भारत को दिया $1.5 अरब का पैकेज

नई दिल्ली। एजेंसी

एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ADB) ने मंगलवार को भारत के लिए 1.5 अरब डॉलर का कोविड 19 पैकेज मंजूर किया। ADB कुछ खास सेक्टरों को और मदद देने के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है। ADB देश के प्राइवेट सेक्टर के भी संपर्क में है ताकि जहां जरूरी हों, वहां सहायता की जा सके।

ADB के वाइस प्रेजिडेंट शिशिन चेन ने ईटी को बताया कि बैंक ने माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को क्रेडिट गारंटी के जरिए सहायता देने के बारे में भारत से चर्चा शुरू कर दी है। यह सहायता मंगलवार को घोषित पैकेज से अलग होगी। उन्होंने कहा, 'कोविड 19 से निपटने और इससे उबरने में अगर और सहायता की जरूरत पड़ी तो ADB देने को तैयार है। हम फाइनेंसिंग के हर विकल्प पर विचार करेंगे।' भारत ADB का चौथा बड़ा शेयरहोल्डर है और करीब 30 अरब डॉलर के कर्ज मिल चुकने के साथ यह इससे सबसे ज्यादा उधार लेने वाला देश भी है। चेन ने कहा कि ADB प्राइवेट सेक्टर से भी बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड और सप्लाई चेन फाइनेंस के अलावा एमएसएमई के लिए हेल्थकेयर, एग्री बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में लिक्विडिटी सपोर्ट पर बात की जा रही है। मंगलवार को घोषित सहायता से पहले हेल्थ, वेलफेयर और इकनॉमी पर कोविड 19 के असर के बारे में सरकार से गहन विचार-विमर्श हुआ था।

इस पैकेज से कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी कदमों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इससे महामारी पर काबू पाने, इससे बचाव के अलावा गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सामाजिक सुरक्षा देने में मदद मिलेगी। इससे पहले इसी महीने वर्ल्ड बैंक ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक अरब डॉलर का पैकेज दिया था। चेन ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2 प्रतिशत के नीचे जा सकती है। एडीबी ने अप्रैल की शुरुआत में दिए गए अनुमान में ग्रोथ 4 प्रतिशत रहने की बात की थी। चेन ने कहा, 'अगर अगले दो महीनों में महामारी पर काबू पा लिया जाए तो इंडियन इकनॉमी अगले वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज करेगी।'

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि यह महामारी कुछ समय बाद फिर कहर ढा सकती है और तमाम देशों को लॉकडाउन हटाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। चेन ने कहा, 'इसका अर्थ यह है कि बार-बार लॉकडाउन करना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को बनाए रखना होगा। इससे सामान्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित होगी और इसका असर इकनॉमिक रिकवरी पर पड़ेगा।'

इकॉनमी को रिवाइव करने के राजकोषीय उपायों के बारे में चेन ने कहा कि महामारी से सर्वाधिक प्रभावित सेक्टरों को सपोर्ट देने के लिए और राहत उपायों की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, एविएशन, ऐग्रिकल्चर और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है।

हेल्थ सर्टिफिकेट, मास्क और ग्लव्स के बिना नहीं हो सकेगी हवाई यात्रा!

मुंबई। लॉकडाउन हटने के बाद जब विमान सेवा दोबारा शुरू होगी तो हवाई यात्रियों को अपने साथ हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर चलना पड़ सकता है। साथ ही, उन्हें यात्रा के दौरान मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप पहनने पड़ सकते हैं और एयरपोर्ट पर उनके शरीर का तापमान भी चेक किया जाएगा। सरकार ने एक टेक्निकल कमिटी बनाई है, जो हवाई सेवाओं और यात्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बना रही है।

फ्लाइट्स की मिडल सीट पर भी बुकिंग मिलेगी!

माना जा रहा है कि कमिटी कोरोनावायरस का प्रसार सीमित करने के लिए जो सिफारिशें करेगी, उसमें ये बातें शामिल होंगी। कमिटी फ्लाइट्स की मिडल सीट पर भी बुकिंग लेने की इजाजत दे सकती है, जो एयरलाइन कंपनियों के लिए बड़ी राहत होगी। लॉकडाउन लागू होने से पहले सरकार ने मिडल सीट खाली रखने का आदेश दिया था, जिसका सभी एयरलाइन कंपनियों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा।

रोकथाम के उपायों पर फोकस

एविएशन मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया कमिटी रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस कमिटी में एयरपोर्ट्स, एयरलाइन कंपनियों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अधिकारी और डॉक्टर शामिल हैं। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'सोशल डिस्टैंसिंग के तहत 6 फुट की शारीरिक दूरी बरतने का जो नियम है, वह मिडल सीट के खाली रखने से पूरा नहीं होना वाला है। यह सीट खाली रखने से यात्रियों के बीच अधिकतम 2 फुट की दूरी होगी। ऐसे में हमारा फोकस रोकथाम के उपायों को लागू करने और सर्टिफिकेट्स पर है, जिससे सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित की जा सके।' अधिकारी ने बताया कि अभी इन उपायों पर चर्चा शुरुआती स्तर पर है।

मिडल सीट खाली रखने से भारी वित्तीय दबाव

एयरलाइन कंपनियों ने मिडल सीट खाली रखने के भारत सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई थी। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चीन में विमान के अंदर सोशल डिस्टैंसिंग बरकरार रखने के लिए विमानन कंपनियां मिडल सीट खाली रखकर उड़ान भर रही हैं। एक सीनियर एयरलाइन एग्जिक्यूटिव ने ईटी को बताया, 'सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों के तहत सुरक्षित फ्लाइट वही होगी, जो 33 पर्सेंट यात्री क्षमता के साथ उड़ान भरेगी। मिडल सीट खाली रखने का सुझाव एयरलाइन कंपनियों के लिए सही नहीं है। इसके उन पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है।'

AC से कोरोना फैलने की नहीं आशंका

अधिकारी ने कहा कि विमान में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना इतना आसान नहीं है। अधिकारी ने कहा, 'एक्सपर्ट्स ने विमानों के एयर कंडिशनर के जरिए कोरोनावायरस फैलने की आशंका से इनकार किया है और एयरक्राफ्ट वायरस को फिल्टर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है।'

कंपनियों ने पकड़ा कन्ज्यूमर के घर का सीधा रास्ता

मुंबई। एजेंसी

हिंदुस्तान यूनिलीवर, ध्रुव, मोंडेलेज, प्रॉक्टर ऐंड गैंबल, डाबर और कोलगेट सहित एक दर्जन से अधिक कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियों ने सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचना शुरू कर दिया है। ये कंपनियां उन क्षेत्रों में ट्रडिशनल ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को दरकिनार कर रही हैं जहां कोविड-19 महामारी की वजह से लास्ट-माइल डिलिवरी बाधित हो गई है।

RWA को भी अपने साथ जोड़ रहीं कंपनियां

कन्ज्यूमर गुड्स कंपनियां इस डायरेक्ट-टु-होम पहल में डुंजो, स्कूट्सी और स्विगी जैसी स्टार्टअप्स से साझेदारी कर रही हैं। वे अपने सेल्स स्टाफ के माध्यम से रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन (RWA) को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। रिटेलर्स सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए यह काम एक महीने पहले से कर रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता हड़बड़ी में राशन जमा करने लगे थे जिससे भीड़ काफी बढ़ गई थी। वहीं फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियां यह काम पहली दफा कर रही हैं।

सहयोग की शक्ति

ITC लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बी सुमंत ने कहा, 'ये साझेदारियां सहयोग की शक्ति का प्रतीक हैं क्योंकि इस अप्रत्याशित समय में ब्रांड के पास अकेले देश की जरूरतों को पूरा करने का दमखम नहीं है।' कोरोना संकट के चलते अधिकतर प्रवासी मजदूर वापस अपने घर चले गए हैं जिससे पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। इसमें रॉ मटीरियल्स की सोर्सिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स की डिलिवरी शामिल है।

ऑनलाइन डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर्स से गठजोड़

डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, 'हम अपने उपभोक्ताओं को जरूरी उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई रणनीति बनाने के साथ नए समाधान तलाश रहे हैं। कंपनी के सेल्स ऑफिशल देशभर के RWS से संपर्क कर रहे हैं और उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं।' डाबर ने रिटेल आउटलेट्स और उपभोक्ताओं के घरों तक सामान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर्स से गठजोड़ किया है।

हाइपरलोकल डिलिवरी प्लैटफॉर्म पर स्टोरफ्रंट

इश्ण्ड कंपनियों ने हाइपरलोकल डिलिवरी प्लैटफॉर्म पर स्टोरफ्रंट बनाए हैं। वे एक्सक्लूसिव ब्रैंड स्टोर्स से और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से ऑर्डर पूरा करने के साथ डिलिवरी पार्टनर्स की मदद से सीधे ग्राहकों के दरवाजे पर सामान पहुंचा रही हैं। फूड ऑर्डरिंग फर्म स्विगी ने अपने स्टोर नेटवर्क नेटवर्क का विस्तार 200 से अधिक शहरों में किया है ताकि उपभोक्ता पड़ोस की दुकानों से राशन ऑर्डर कर सकें।

उपभोक्ताओं को सहूलियत, डिलिवरी पार्टनर्स की कमाई

स्विगी के प्रवक्ता ने कहा, 'इस साझेदारी के माध्यम से हम अपनी हाइपरलोकल डिलिवरी को नया आयाम दे रहे हैं। इससे हमारे उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी और हमारे डिलिवरी पार्टनर्स की कमाई भी बढ़ेगी।' कंपनियां अभी साफतौर पर नहीं बता पा रही हैं कि क्या इस तरह की पहल उनकी सप्लाई चेन का नियमित हिस्सा बना जाएगी जो परंपरागत तौर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स पर निर्भर रहती है, जबकि वे मैन्युफैक्चरिंग और ब्रैंड्स के प्रमोशन पर फोकस करती हैं।

5G नेटवर्क की तैयारी

एयरटेल और नोकिया में 7,500 करोड़ रुपये की डील

नई दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया को भारती एयरटेल से 5जी नेटवर्क तैयार के लिए 7,500 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इसके तहत कंपनी देश के नौ दूरसंचार सर्किलों में ये नेटवर्क तैयार करेगी। भारती एयरटेल ने मंगलवार को बताया कि इस ठेके के तहत नोकिया 4जी सेवाओं के लिए तीन लाख बेस स्टेशन तैयार करेगी, जिसे अगली पीढ़ी की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम मिलने के बाद 5जी नेटवर्क में अपग्रेड किया जा सकेगा। भारती एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता और ग्राहकों की सुविधा बेहतर बनाने के लिए यह ठेका दिया है। एयरटेल ने इन नौ दूरसंचार सर्किलों में नोकिया की सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क (एसआरएएन) प्रौद्योगिकी के लिए कई वर्षों का समझौता करने की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक इस ठेके का मूल्य करीब 7,500 करोड़ रुपये है। एयरटेल ने एक बयान में कहा कि इन उपकरणों के माध्यम से भविष्य में 5जी सेवाएं देने में मदद मिलेगी। इसके तहत एयरटेल के इन नौ सर्किल में करीब तीन लाख रेडियो नटवर्क उपकरण लगाए जाएंगे। यह इस साल का पहला नेटवर्क विस्तार सौदा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान तेज गति वाले डाटा की मांग करीब 20 प्रतिशत बढ़ी है। भारती एयरटेल ने बयान में कहा कि हम ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं मुहैया कराने के लिए नई प्रौद्योगिकी में लगातार निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नोकिया के साथ यह पहल इस दिशा में एक बड़ा कदम है।

इन देशों में शुरू हो चुकी है 5जी सेवा

5जी सर्विस अमेरिका में कुछ जगह पर शुरू हो चुकी है। साथ ही कुछ यूरोपियन देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनके नाम स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और ब्रिटेन हैं। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, स्पेन, स्वीडन, कतर और यूएई ने 5जी को शुरू करने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है।

4जी से 5जी कितना अलग

5जी तकनीक पूरी तरह से 4जी तकनीक से अलग होगी। यह सब कुछ टेलीकॉम कंपनियों के निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। फिलहाल 4जी पर सर्वाधिक 45 एमबीपीएस की स्पीड मुमकिन है और एक चिप निर्माता कंपनी का अनुमान है कि 5जी टेक्नोलॉजी इससे 10 से 20 गुना तक अधिक स्पीड दे सकेगी।

कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए IIT और हेस्टर ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 के खात्मे को लेकर दुनियाभर के वैज्ञानिक उपाय ढूढ़ने में लगे हैं। अलग-अलग देशों में वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में दिन-रात जुटे हुए हैं, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस बीच भारत में भी कोविड-19 वैक्सीन बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। अहमदाबाद की दवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज ने बुधवार को कहा कि उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटीजी) के साथ मिलकर COVID-19 का टीका विकसित करेगा। इसके लिए दोनों संगठनों के बीच 15 अप्रैल 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कंपनी ने कहा है कि यह टीका पुनः संयोजक एवियन पैरामाइक्सोवायरस आधारित वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा।हेस्टर बायोसाइंसेस के सीईओ और एमडी राजीव गांधी ने कहा, 'आईआईटी गुवाहाटी और हेस्टर दोनों मिलकर कोविड-19 को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन को विकसित करने और इसे बनाने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। हेस्टर की भागीदारी मास्टर सीड के विकास से लेकर कामर्शियल रूप में वैक्सीन जारी करने तक होगी।' बयान के मुताबिक रीकॉम्बिनेंट एवियन पैरामिक्सोवायरस-1 का उपयोग 'सार्स-कोव-2 के एक इम्यूनॉजिक (शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जगाने वाले) प्रोटीन के तौर पर किया जाएगा। बाद में इसका उपयोग आगे के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। इस बारे में हेस्टर बायोसाइंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव गांधी ने कहा, "कंपनी और आईआईटी-गुवाहाटी मिलकर कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए एक रीकॉम्बिनेंट टीका विकसित करेंगे। इसका विनिर्माण एक रक्षोपाय के तौर पर किया जाएगा। हेस्टर टीके के विकसित करने के शुरूआती चरण से लेकर इसके वाणिज्यिक स्तर पर जारी होने तक काम करेगी। इस टीके की क्षमता के बारे में आईआईटी गुवाहाटी के जैवशास्त्र और जैवप्रौद्योगिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर सचिन कुमार ने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वह अनुसंधान टीम के प्रमुख होंगे। बता दें दुनिया भर में 3,138,413 लोगों को को बीमार करने वाला कोरोना अब तक 217,985 लोगों की जान ले चुका है। भारत में भी पिछले 12 घंटे में कोरोना वायरस के 1358 नए मामले सामने आए हैं, वहीं सबसे अधिक 70 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 31332 हो गई है। वहीं, इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1007 पहुंच गया है।

गेहूँ की सरकारी खरीद जोरों पर, आंकड़ा 88.6 लाख टन पहुँचा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन में भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं खरीद का काम तेज गति से हो रहा है तथा चालू विपणन वर्ष में अभी तक 88.6 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीद लक्ष्य विपणन वर्ष 2020-21 अप्रैल-मार्च के लिए 4.07 करोड़ टन निर्धारित किया गया है जहां रिकॉर्ड 10 करोड़ 62.1 लाख टन का उत्पादन होने की संभावना है। सरकार थोक में गेहूं की खरीद अप्रैल-जून के तीन महीनों में करती है। सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद कार्य को अंजाम देती हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 वायरस के प्रसार के बढ़ते खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के साथ खरीदकार्य हो रहा है।" मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी प्रमुख खरीद करने वाले राज्यों में गेहूं की खरीद 'बहुत तेज गति' से हो रही है। 26 अप्रैल को केंद्रीय पूल के लिए कुल 88.6 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। इसमें सर्वाधिक योगदान पंजाब का 48.2 लाख टन का है, इसके बाद हरियाणा का 19 लाख टन का योगदान है। मंत्रालय ने कहा, " वर्तमान रफ्तार से चार करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी संभावना है।" मंत्रालय ने कहा कि अब तक, सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 58.4 लाख टन अनाज अनाज की निकासी की गयी है। इसके लिए मालगाड़ियो के कुल मिला कर 2,087 रैक लगा गए। ऐसी उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील के साथ, आने वाले दिनों में उतराई की गति और बढ़ेगी। राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब योजना (पीएमजीएवाई) के तहत मुफ्त वितरण के लिए खाद्यान्न उठाने के बारे में, मंत्रालय ने कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और लक्षद्वीप में 'अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है' जहां तीन महीने का पूरा कोटा उठा लिया गया है। अन्य सात राज्य जून महीने का कोटा उठा रहे हैं जबकि 20 राज्य अभी मई महीने का कोटा उठा रहे हैं। आठ राज्यों में अप्रैल महीने का कोटा उठाया जा रहा है, जो महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कोई गरीब भूखा न रहे, सरकार पीएमजीएवाई के तहत तीन महीने के लिए प्रति राशन कार्ड धारक को लगभग पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले कोटे के अलग और अधिक है।

क्या आप जानते हैं?

किस देवता को कौन सा फूल पसंद है

हिंदू धर्म में विभिन्न फूलों का विशेष महत्व है। धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, आरती आदि कार्य बिना फूल के अधूरे ही माने जाते हैं। फूलों के संबंध में शारदा तिलक नामक पुस्तक में कहा गया है-दैवस्य मस्तकं कुर्यात्कुसुमोपहितं सदा। अर्थात- देवता का मस्तक सदैव पुष्प से सुशोभित रहना चाहिए। वैसे तो किसी भी भगवान को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ फूल देवताओं को विशेष प्रिय होते हैं। इन फूलों का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। देवताओं को उनकी पसंद के फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस देवता के पूजन में कौन से फूल चढ़ाना चाहिए-

भगवान श्रीगणेश- आचार भूषण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्रीगणेश को तुलसीदल को छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढाएं जा सकते हैं। पद्मपुराण आचाररत्न में भी लिखा है कि 'न तुलस्या गणाधिपम'अर्थात् तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। दूर्वा के ऊपरी हिस्से पर तीन या पांच पत्तियां हों तो बहुत ही उत्तम है।

भगवान शिव- भगवान शंकर को धतूरे के फूल, हरसिंगार, व नागकेसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल गट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के फूल चढ़ाने का विधान है। भगवान शिव को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है।

भगवान विष्णु- इन्हें कमल, मौलसिरी, जूही, कदम्ब, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजयंती के पुष्प विशेष प्रिय हैं। विष्णु भगवान तुलसी दल चढ़ाने से अति शीघ्र प्रसन्न होते है। कार्तिक मास में भगवान नारायण केतकी के फूलों से पूजा करने से विशेष रूप से प्रसन्न होते है । लेकिन विष्णु जी पर आक, धतूरा, शिरीष, सहजन, सेमल, कचनार और गूलर आदि।

सूर्य नारायण- इनकी उपासना कुटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक, अशोक आदि के पुष्प भी इन्हें प्रिय हैं।

भगवान श्रीकृष्ण- अपने प्रिय पुष्पों का उल्लेख महाभारत में युधिष्ठिर से करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं- मुझे कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश व वनमाला के फूल प्रिय हैं।

भगवती गौरी- शंकर भगवान को चढ़ने वाले पुष्प मां भगवती को भी प्रिय हैं। इसके अलावा बेला, सफेद कमल, पलाश, चंपा के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं।

लक्ष्मीजी- मां लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल है। उन्हें पीला फूल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी काफी प्रिय है।

हनुमान जी- इनको लाल पुष्प बहुत प्रिय है। इसलिए इन पर लाल गुलाब, लाल गेंदा आदि पुष्प चढ़ाए जा सकते है।

मां काली - इनको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। मान्यता है की इनको 108 लाल गुड़हल के फूल अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है।

मां दुर्गा- इनको लाल गुलाब या लाल अड़हुल के पुष्प चढ़ाना श्रेष्ठ है।

मां सरस्वती- विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले रंग का फूल चढ़ाए जाते हैं। सफेद गुलाब, सफेद कनेर या फिर पीले गेंदे के फूल से भी मां सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं।

शनि देव- शनि देव को नीले लाजवन्ती के फूल चढ़ाने चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी नीले या गहरे रंग के फूल चढ़ाने से शनि देव शीघ्र ही प्रसन्न होते है।

ध्यान रखने योग्य बातें

■भगवान की पूजा कभी भी सूखे व बासी फूलों से न करें।

■कमल का फूल को लेकर मान्यता यह है कि यह फूल दस से पंद्रह दिन तक भी बासी नहीं होता।

■चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली देवताओं को अर्पित नहीं की जानी चाहिए।

■आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी-देवताओं को अर्पित करना चाहिए।

■तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है।

■शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र छह माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है।

पूजा कर रहे हैं तो रखें ध्यान

इन 10 सामग्रियों को भूलकर भी न रखें जमीन पर

हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रहता है कि हम अनजाने में कौन सी गलतियां कर रहे हैं। वास्तव में हमारा ध्यान सिर्फ भगवान पर ही होता है। आइए ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार जानते हैं कि पूजन के दौरान कौन-कौन सी चीजें सीधे जमीन पर नहीं रखनी चाहिए।

1- दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखने चाहिए या लकड़ी के बाजोट पर दीपक रखना चाहिए।

2- पूजा में सुपारी को सिक्के के ऊपर रखना चाहिए। इसे भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए।

3- शालिग्राम को भी जमीन पर न रखें। बल्कि इसे साफ रेशमी कपड़े पर रखना चाहिए।

4- यदि आप पूजा में कोई मणि या रत्न रखना चाहते इसे भी किसी साफ कपड़े पर ही रखें।

5- देवी-देवताओं की मूर्तियां भी कभी फर्श पर नहीं रखी जाती हैं। लकड़ी या सोने-चांदी के सिंहासन या बाजोट पर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए।

6- देवी-देवताओं के वस्त्र और आभूषण जमीन पर वस्त्र रखने से गंदे हो जाते हैं। भगवान को हमेशा पवित्र वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए इसलिए वस्त्र और आभूषण को भी जमीन पर नहीं रखा जाता है।

7- जनेऊ को साफ कपड़े पर रखना चाहिए, क्योंकि इसे देवताओं को मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है।

8- शंख को लकड़ी के फट्टे पर या साफ कपड़े पर रखा जाता है।

9-फूल भी कभी जमीन पर न रखें इन्हें किसी पवित्र धातु या स्वच्छ पात्र में ही रखें।

10-पानी का कलश जमीन के बजाय थाली में रखें।

वेदों के साथ-साथ देवों और महापुरुषों ने भी किया है गौमाता का बखान

हिन्दू धर्म में गाय पूजनीय है और इसमें तैंतीस करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हिन्दू धर्मग्रन्थों और वेदों में तो गाय को स्थान दिया ही गया है, देवों और महापुरुषों ने भी गाय का उत्तम बखान किया है। आइए जानते हैं किसने क्या कहा है गाय के बारे में -

■स्कंद पुराण के अनुसार 'गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगौमय हैं।'

■भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद्गीता में कहा है- 'धेनुनामस्मि कामधेनु' अर्थात मैं गायों में कामधेनु हूं।

■ईसा मसीह ने कहा था- एक गाय को मारना एक मनुष्य को मारने के समान है।

■श्रीराम ने वन गमन से पूर्व किसी त्रिजट नामक ब्राह्मण को गाय दान की थी।

■गुरु गोविंदसिंहजी ने कहा, 'यही देहु आज्ञा तुरुक को खापाऊं, गौ माता का दुःख सदा मैं मिटाऊं।'

■ बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि 'चाहे मुझे मार डालो, पर गाय पर हाथ न उठाओ'।

■प्रसिद्ध मुस्लिम संत रसखान की इच्छा थी कि यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं बाबा नंद की गायों के बीच में जन्म लूं।

■पं. मदनमोहन मालवीय की अंतिम इच्छा थी कि भारतीय संविधान में सबसे पहली धारा सम्पूर्ण गौवंश हत्या निषेध की बने।

■पंडित मदनमोहन मालवीय का कथन था कि यदि हम गायों की रक्षा करेंगे तो गाएं हमारी रक्षा करेंगी।

■महर्षि अरविंद ने कहा था कि गौ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धात्री होने के कारण कामधेनु है। इसका अनिष्ट चिंतन ही पराभव का कारण है।

■मुस्लिम कवि रसखान ने कहा- 'जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन।'

■महात्मा नामदेव ने दिल्ली के बादशाह के आह्वान पर मृत गाय को जीवनदान दिया।

■भगवान बुद्ध को गाय के पास उस क्षेत्र के सरदार की बेटी सुजाता द्वारा गायों के दूध की खीर खानें पर तुरन्त ज्ञान और मुक्ति का मार्ग मिला। बुद्ध गायों को मनुष्य की परम मित्र कहते हैं।

■जैन आगमों में कामधेनु को स्वर्ग की गाय कहा गया है और प्राणिमात्र को अवध्या माना है। भगवान महावीर के अनुसार गौ रक्षा बिना मानव रक्षा संभव नहीं।

■स्वामी दयानन्द सरस्वती कहते हैं कि एक गाय अपने जीवनकाल में 4,10,440 मनुष्यों हेतु एक समय का भोजन जुटाती है जबकि उसके मांस से 80 मांसाहारी लोग अपना पेट भर सकते हैं।

■गांधीजी ने कहा है कि गोवंश की रक्षा ईश्वर की सारी मूक सृष्टि की रक्षा करना है, भारत की सुख- समृद्धि गाय के साथ जुड़ी हुई है। गाय प्रसन्नता और उन्नति की जननी है, गाय कई प्रकार से अपनी जननी से भी श्रेष्ठ है।

■इस प्रकार से देवों, वेदों, महापुरुषों एवं आम जनों में गाय का महत्व अत्यधिक है।

छोटे दुकानदारों ने भी खटखटाया वित्त मंत्री का दरवाजा, विशेष पैकेज की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मांगने वालों में अब छोटे कारोबारी या दुकानदार भी शामिल हो गए हैं। इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि लॉकडाउन का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे कारोबारियों ने ही उठाया है, इसलिए इनके लिए तुरंत आर्थिक पैकेज घोषित होना चाहिए।

तुरंत हो पैकेज की घोषणा

छोटे कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि अब देश के व्यापारी और अधिक इंतजार नहीं कर सकते और अब वह समय आ गया है, जब सरकार को व्यापारियों के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा तुरंत करनी चाहिए। उनका कहना है कि देश भर में व्यापारी वर्ग ही ऐसा है, जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कैट ने कहा है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों के लिए कई पैकेजों की घोषणा की है, लेकिन व्यापारिक समुदाय जिसे अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। इसलिए उनकी हालत बेहद पतली हो गई है। कैट ने यह भी कहा कि अगर व्यापारियों को पर्याप्त पैकेज नहीं दिया जाता है, तो देश में घरेलू व्यापार काफी हद तक ध्वस्त हो सकता है। उनका कहना है कि देश में कृषि के बाद खुदरा व्यापार सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, इस क्षेत्र को राहत प्रदान करना बहुत आवश्यक है।

'कोरोना व्यापारियों के लिए अकाल जैसा'

कैट का कहना है कि जब देश में अकाल पड़ता है तो सरकार किसानों को पैकेज देती है। कोरोना संकट देशभर के व्यापारियों के लिए एक अकाल ही है, जिसे देखते हुए सरकार को व्यापारियों के लिए एक आर्थिक पैकेज तुरंत देना चाहिए। इसलिए अब उनकी आस केंद्रीय वित्त मंत्री पर ही टिकी है।

'व्यापारियों ने जीवन जोखिम में डाला'

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, 'कोरोना महामारी के इस विकट समय में देश भर के लगभग 45 लाख व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे देश में किसी भी सामग्री की कोई कमी कहीं नहीं हुई है। व्यापारियों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला और भारत के नागरिकों की सेवा की है। इसलिए अगर व्यापारियों को कोई पैकेज नहीं दिया जाता है, तो भारत में खुदरा व्यापार व्यवसाय अपने सबसे बुरे दिन देखेगा और बड़ी संभावना इस बात की है कि देशभर में बड़ी संख्या में व्यापारी खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री से विशेष आग्रह किया गया है कि इनके लिए तत्काल पैकेज घोषित किया जाए।'

सरकार लाई फ्लिपकार्ट-अमेजन का देसी वर्जन, घर-घर पहुंचेगा सब्जी-दूध

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

ये देसी है, फ्लिपकार्ट और अमेजन (Desi Amazon Flipkart) का रूरल वर्जन और सरकार इसे प्रमोट कर रही है। लॉकडाउन (Lockdown in india) के चलते जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने गांव के लेवल पर एक ऑनलाइन रिटेल चेन बनाई है। इसमें सरकार ने तेजी से बढ़ रहे आउटलेट्स को जोड़ा है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर लेंगे और होम डिलीवरी करेंगे।

इस प्लान को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Center) को जोड़ा है। इस तरह सरकार 3.8 लाख आउटलेट्स के जरिए करीब 60 करोड़ ग्रामीण लोगों तक अपनी पहुंच बना रही है। सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा है कि ये आउटलेट्स लोगों के निजी आउटलेट हैं, लेकिन सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे। सरकार की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर्स को सब्जियां, दूध, दालें, फल और अन्य प्रोडक्ट की सेल और सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है।

ऐप से या ऑफलाइन कर सकते हैं ऑर्डर

ग्राहक ऑनलाइन जाकर लोगों के लिए बनाए गए ऐप से सामान ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऐप ग्रामीण लेवल के एंट्राप्रेन्योर्स को दिए गए हैं। या ये ऐप उन्हें दिए गए हैं जिन्हें रिटेल और अन्य कॉमन सर्विस सेंटर्स की एक्टिविटी का चार्ज दिया गया है। ये ग्रामीण लेवल के एंट्राप्रेन्योर्स ऑफलाइन ऑर्डर भी लेते हैं और फिर सामान को कुछ घंटे से लेकर एक दिन के अंदर-अंदर ग्राहक तक पहुंचाने का इंतजाम करते हैं।

2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स जुड़े

दिनेश त्यागी ने बताया कि ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे हैं, लेकिन सिर्फ गांव वालों के लिए हैं। हमने ये कदमम करीब 3 हफ्ते पहले लिया था और अब तक हम इसमें करीब 2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को जोड़ चुके हैं।

12 करोड़ लोगों पर वायरस की मार, कमाई का जरिया छिना

बेंगलुरु। एजेंसी

देशभर में घोषित लॉकडाउन के चलते पिछले एक महीने से लगभग 10 से 12 करोड़ ब्लू कॉलर वर्कर्स को कोई आमदनी नहीं हो सकी है। इंडस्ट्री में इन वर्कर्स की लगभग 70-80 पर्सेंट हिस्सेदारी है। यह जानकारी स्टाफिंग एजेंसियों और कंपनियों ने दी है। इस सेक्टर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस साल की आगामी तिमाहियों में नौकरियां घट सकती हैं। उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने पर ही कुछ राहत मिल सकती है। ब्लू कॉलर वर्कर्स को कंपनियों के साथ जोड़ने वाली कंपनी बेटरप्लेस के को-फाउंडर प्रवीण अग्रवाल ने कहा, 'स्लोडाउन मार्च के मध्य से शुरू हुआ और लगभग 2-3 करोड़ लोगों के पास ही नौकरियां बची हैं।' स्टाफिंग एजेंसी टीमलीज ने कहा कि ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन, रिटेल और आउटडोर एंटरटेनमेंट, फूड और बेवरेज और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इसके अलावा ऑटोमोटिव, गैर जरूरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पोल्ट्री, डेयरी, शिपिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसका असर दिखेगा। टीमलीज की कोफाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, 'इन सेक्टरों पर लॉकडाउन का असर दिखेगा ही और हमें अब तक इनमें से किसी में भी स्थिति सुधरती नहीं दिखी

है। कई फॉर्मल सेक्टर्स पर अभी पूरा असर इस वजह से नहीं दिखा है क्योंकि इनके ज्यादातर कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान भी पूरी और समय पर सैलरी मिली है।'

उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन हटने के बाद अधिक चुनौतियां आएंगी। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स लॉकडाउन शुरू होने के बाद से बिना रोजीरोटी के गुजर-बसर कर रहे हैं। उनके लिए तो हर दिन चुनौती ही है।' कॉन्ट्रैक्ट एंप्लॉयीज में से अधिकतर को घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलती है लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी न के बराबर कमाई हुई है। बिजनस बंद होने के चलते ड्राइवर, डिलिवरी स्टाफ, सेल्स और बिजनस डिवेलपमेंट एंप्लॉयीज को एक से तीन महीने की तनख्वाह देकर रातोंरात नौकरी से निकाल दिया गया है। स्टाफिंग एजेंसियों का कहना है कि नई उभरती कंपनियां जैसे बिजनस-टू-बिजनस ईकॉमर्स प्लैटफॉर्म उड़ान, फूड डिलिवरी ऐप स्विगी, सोशल कॉमर्स वेंचर मीशो और लॉजिस्टिक फर्म ब्लैक-बक के साथ कुछ पारंपरिक सेक्टर्स ने भी पिछले कुछ हफ्तों में कॉन्ट्रैक्ट एंप्लॉयीज को हटाया है। ब्लू कॉलर सेगमेंट का ही हिस्सा शेयर्ड मोबिलिटी और ईकॉमर्स स्टाफ समेत गिग इकॉनमी वर्कफोर्स की आमदनी 60-70 पर्सेंट घटी है। सर्विसेज मार्केटप्लेस अर्बनक्लैप और स्विगी जैसी कंपनियों के एंप्लॉयीज ने कहा कि बिजनेस धीरे-धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन मांग 40-50 पर्सेंट कम है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि दशहरा तक डिमांड में उछाल नहीं आने पर कर्मचारियों की संख्या या तो स्थिर रहेगी या साल के अंत तक और कम हो जाएगी।

वर्चुअल हियरिंग से हो सकेगा टैक्स अपीलों का निपटारा

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन के बीच अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की पहल के बाद अब सरकार ने स्थानीय टैक्स प्रशासन और ज्यूडिशियल टैक्स अथॉरिटीज के स्तर पर अपीलों की सुनवाई भी वर्चुअल मोड में करने का रास्ता दिखा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने मंगलवार को एक गाइडलाइन जारी कर फील्ड ऑफिस या अथॉरिटीज में पर्सनल हियरिंग, अपीलों पर सुनवाई और फैसलों के तौर-तरीके साफ कर दिए। इसके तहत जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले अधिकारियों, कारोबारियों, वकीलों, सीए या प्रतिनिधि का सही ड्रेस में होना जरूरी है, वहीं पहचान और गोपनीयता भी कायम रखनी होगी। सीबीआईसी ने यह गाइडलाइंस कस्टम एक्ट 1962 के तहत जारी की है, लेकिन एक्साइज और सर्विस टैक्स कानूनों के तहत अपीलें भी इसके दायरे में होंगी। कई राज्यों में एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज (ARR) ने पहले ही जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों पर वीडियो के जरिए फैसले देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर लेवल पर होने वाली पर्सनल हियरिंग और अपीलों की सुनवाई भी वर्चुअल मोड में हो सकेगी। गाइडलाइन के मुताबिक अपील से पहले वादी और प्रतिवादी दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई पर लिखित सहमति देनी होगी। इसके बाद सभी पार्टियों को सुनवाई का समय, तारीख और वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा। पार्टी की ओर से पेश होने वाले वकील, कंसल्टेंट या अधिकृत व्यक्तियों को आईडी प्रूफ के साथ ऑथराइजेशन लेटर पेश न्यायिक अथॉरिटी को पेश करना होगा। ड्रेस और डिकोरम मेंटेन करना होगा। अपीलेट अथॉरिटी की ओर से कही गई बातों को पर्सनल हियरिंग रिकॉर्ड के तौर पर लिखित रूप दिया जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी अपीलेंट को ई-मेल की जाएगी, जिसे वह किसी और को शेयर नहीं करेगा। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया वाजिब दस्तावेजों के साथ तीन दिन में मेल करनी होगी। इस अवधि के बाद यह मान लिया जाएगा कि वह ईमेल के रिकॉर्ड से सहमत है। फिर इसे फैसले के लिए भेज दिया जाएगा। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के मेंटर बिमल जैन ने कहा, 'इसकी सख्त जरूरत थी। लॉकडाउन के बीच इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को अपील करने और उसके त्वरित निपटारे की दिशा में यह अनूठी पहल तो है ही, जीएसटी, एक्साइज, सर्विस और वैट विवादों की पर्सनल सुनवाई के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।' सभी प्रशासनिक इकाइयों को तकनीकी सुविधाएं बहाल करने को भी कहा गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि इसका मकसद कोविड-19 के प्रभाव के दौरान कर न्याय प्रक्रिया ठप नहीं होने देना और सुनवाई में तेजी लाना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की हालिया गाइडलाइन का भी ध्यान रखा गया है।

वैश्विक उद्योग संगठनों की भारत से समानीकरण शुल्क नौ माह टालने की मांग

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेशी कंपनियों के संगठनों ने कोविड- 19 महामारी के प्रसार को देखते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गैर- निवासी ई- वाणिज्य कंपनियों पर लगाये गये दो प्रतिशत इक्वलाइजेशन (समानीकरण) कर को नौ माह टालने की गुहार लगाई है। वॉलमार्ट, अमेजन, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी वैश्विक ई-वाणिज्य कंपनियां इन संस्थाओं की सदस्य हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद, जापान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंफार्मेशन टैक्नालॉजी इंडस्ट्रीज एसोसिसन, एशिया प्रशांत एमएसएमई व्यापार गठबंधन और डिजिटल यूरोप सहित नौ व्यावसायिक संस्थाओं के समूह ने सरकार से समानीकरण शुल्क (दो प्रतिशत कर) पर विचार करने की मांग की है। यह शुल्क सरकार ने इसी वित्त वर्ष में लगाया है। अमेरिका, यूरोपीय, आस्ट्रेलियाई और एशिया क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली इन व्यावसायिक संस्थाओं ने संयुक्त पत्र भेजकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित जी20 समूह के नेताओं द्वारा व्यक्त मुक्त, उचित, निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय और स्थिर व्यापार और निवेश परिवेश उपलब्ध कराये जाने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया है। इन संस्थाओं का कहना है कि जी20 देशों के नेताओं ने वैश्विक बाजारों को खुला और भेदभाव रहित रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस संयुक्त पत्र में इन संस्थाओं ने कहा है, ''अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति की गई इस प्रतिबद्धता को संज्ञान में लेते हुये पूरे सम्मान के साथ हम समानीकरण शुल्क लगाये जाने के मामले में औपचारिक स्तर पर संबंधित पक्षकारों के साथ विचार विमर्श करने और केन्द्र सरकार के वित्त विधेयक 2020 की धारा 165ए में लगाये गये शुल्क के क्रियान्वयन को कम से नौ माह टालने का आग्रह करते हैं।'' पत्र में कहा गया है कि धारा165ए के तहत भारत की मौजूदा समानीकरण शुल्क के तहत दो प्रतिशत का नया शुलक लगाकर इसे विस्तारित किया गया है।

कोरोना काल से स्वःसहायता समूह के बदले हालात

इंदौर। एजेंसी

कारोना काल में हर कोई बाहर निकलना चाहता है परन्तु लॉक डाउन की वजह से सभी को हर समय घर पर ही रहना पड़ रहा है, केवल अतिआवष्यक कार्य के लिये बाहर जाने का मिल रहा फिर वापस घर पर। कोरोना काल में समाज के लिये सभी एक साथ एक टीम की तरह लोगो के लिये मास्क, भोजन की व्यवस्था कर रहे तो वही कुछ महिलाये अपने घर पर मास्क बना कर उन गरिबो को दे रही जिनके पास मास्क नही है और वे ये सब खरीदने में असमर्थ है।

हिण्डालको महान द्वारा महिलाओ के स्वावलम्बन हेतु संचातिल दिव्य महिला स्वःसहायता समूह जिसमें महिलाओ के द्वारा मच्छरदानी की जगह पर अभी वर्तमान समय में प्रतिदिन मास्क का निर्माण किया जा रहा है और उन गरिब लोगो तक पहुंचाया जा रहा है जिनके पास मास्क नही है। यह लॉकडाउन दिव्य महिला स्वःसहायता समूह के लिये सुनहरे अवसर के रुप में आया है जो देष की सेवा के साथ-साथ घर खर्च हेतु अपनी आय भी कमा ले रही है।

दिव्य महिला स्वःसहायता समुह हिण्डालको महान सी.एस.आर. कि देन है जिन्होने महिलाओ हेतु जागरुकता व सशक्तिकरण कार्यकम कर उनको अपने पैरो खड़ा होने के लिये शिक्षा हेतु कोचिंग सेन्टर, सिलाई सेन्टर, ब्यूटीपार्लर, पौढ़ षिक्षा के साथ-साथ समूह संगठन का निर्माण जिससे महिलाये स्वावलम्बन हो सके और अपने घर का खर्च उठा सके। महान सी.एस.आर. द्वारा महिला समूह में कोरोना के चलते प्रतिदिन मास्क बनाये जा रहे और जरुरत के तहत उसका वितरण किया जा रहा है। यह महिलाये प्रतिदिन 500 से ज्यादा मास्क का निर्माण करती है। कोरोना की महामारी में ये महिलाये घर खर्च के लिये पैसे कमा लेती है और अपने जीवनयापन के साथ-साथ समाज के बारे में भी सोच रही है।

दिव्य महिला स्वःसहायता समूह के द्वारा बने हुये मास्क महान सी.एस.आर. के माध्यम से गांव के साथ-साथ वनांचलो क्षेत्र में भी जहां पहाडो पर निवासरत आदिवासी रहते है उन्हे इस मास्क के बारे में अवगत कराकर इससे हम खुद को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते है की जानकारी दी। महिला दिव्य स्वःसहायता समुह में कुछ महिलाये ऐसी भी है जो महान द्वारा संचालित सिलाई प्रषिक्षण केन्द्र में प्रषिक्षण प्राप्त की है और इस संगठन का हिस्सा बनी है।

हिण्डालको महान सी.एस.आर. के द्वारा संचालित सहायता समूह में महिलाओ के द्वारा बैग, मच्छरदानी, बनाइ जाती थी पर इस कोराना काल में इन महिलाओ के द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है जो अलग-अलग सुन्दर रंगो में बनायी गयी है एवं इसका इस्तेमाल इसे धोकर भी किया जा सकता है। इस प्रकार से इस कोरोना काल में दिव्य महिला स्वःसहायता समूह के द्वारा बनाये हुये मास्क महान सी.एस.आर. प्रतिदिन लोगो में बांटकर "हम इस कोरोना महामारी की लड़ाई में आपके साथ है" का संदेष दे रहे है। साथ ही हिण्डालको महान सी.एस.आर. महिला दिव्य स्वःसहायता समूह की महिलाओ को मास्क निमार्ण हेतु धन्यवाद देता है।

कार्पोरेट कंपनियों ने कोविड-19 की तेज जांच के लिए आधुनिक मशीनें दान दी मप्र सरकार को

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के नमूनों की तेजी से जांच करने के लिए प्रिज्म सीमेंट और यश टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने प्रदेश सरकार को आधुनिक जांच मशीनें दान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के लिए कोविड-19 के मरीजों की तेजी से जांच करना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2165 मरीज पाए गए हैं और इनमें से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सीएसआर) के तहत प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की इकाई प्रिज्म सीमेंट और इन्दौर की यश टेक्नॉलाजी ने दो उच्च क्षमता वाली उन्नत जांच मशीनें दान करेंगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि कोरोना नमूनों की जांच के लिए यह मशीनें इन्दौर और भोपाल के मेडिकल कॉलेज में लगाई जायेंगी। शुक्ला ने बताया कि प्रारंभ में यह कंपनियां मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की योजना बना रही थीं लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि ये कंपनियां नकद धनराशि के बजाय कोरोना की जांच मशीनें दान में दे सकती हैं। इससे कोरोना के इस संकट समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में तेजी आ सकेगी। शुक्ला ने बताया कि इन आधुनिक मशीन की क्षमता 800 से 1000 परीक्षण प्रतिदिन करने की है। उन्होंने बताया कि इन्दौर और भोपाल में ये मशीनें आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वर्धमान ग्रुप, डालमिया सीमेंट और वेलस्पन ने प्रदेश में कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए ऐसी मशीनें प्रदेश सरकार को दान देने का फैसला किया है। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के नीलमणि सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोविड- 19 की परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के प्रिज्म सीमेंट डिविजन ने प्रदेश सरकार को एक उच्च गति कोरोना वायरस मशीन सीएसआर के तहत योगदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सिंगापुर में निर्मित यह मशीन आरटी पीसीआर सिस्टम क्वांट स्टैडियो 7 फ्लेक्स सिस्टम विथ एंसिलरीज मशीन वर्तमान में उपलब्ध सबसे उन्नत मशीनों में से एक है और प्रति दिन लगभग 1000 परीक्षण कर सकती है। मशीन की लागत लगभग 65 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि यह मशीन सरकार को जल्दी और सटीक रूप से रोगियों का परीक्षण करने और संक्रामक वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। सिंह ने बताया कि मशीन प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है और इसे कोरोना वायरस की जांच के लिए भोपाल के गांधी मेडीकल कॉलेज में स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना की जांच में तेजी जायेगी और नमूनों की जांच लंबित नहीं होगी इससे कोरोना प्रभावित मरीजों का उपचार जल्द शुरु हो सकेगा।

मात्र 2 सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर खुल जाएगा बिजली बिल

एन से प्रारंभ होगा शहर के उपभोक्ताओं का आईवीआरएस नंबर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने स्वयं के बनाए नेक्स्ट जनरेशन बिलिंग सॉफ्टवेअर पर इंदौर शहर के बिलों के डाटा की शिफ्टिंग चालू कर दी है। इस माइग्रेशन प्रक्रिया के बाद मई से इंदौर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं को और भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। मात्र 2 सेकंड में बिल मोबाइल की स्क्रीन पर खुल जाएगा। 10 से 15 सेकंड में उपभोक्ता बिल भर भी सकेंगे। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल ने बताया कि नए बिलिंग सॉफ्टवेअर में 25 अप्रैल तक इंदौर शहर को छोड़कर शेष 14 सर्कल के करीब 47 लाख उपभोक्ताओं डाटा माइग्रेट हो चुका है। इन उपभोक्ताओं के 10 अंकों के ग्राहक संख्या नंबर अंग्रेजी अक्षर एन से प्रारंभ हो रहे हैं, इसके बाद 10 अंक है। श्री नरवाल ने बताया कि अब इंदौर के दक्षिण शहर संभाग के उपभोक्ताओं को नए बिलिंग सॉफ्टवेअर के साथ जोड़ा जा रहा है। यहां मई में जारी होने वाले बिल नए सॉफ्टवेअर से मिलेंगे। जून तक शहर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य संभाग के अन्य 5.15 लाख उपभोक्ता भी नए सॉफ्टवेअर से बिल प्राप्त करने लगेंगे। मप्रपक्षेविविकं के स्वयं के एनजीबी सॉफ्टवेअर का डाटा सेंटर इंदौर ही होने से उर्जस मोर्बाइल एप व पोर्टल पर पूरा बिल मात्र 2 सेकंड में खुलेगा। आगे जाकर इस सॉफ्टवेअर के माध्यम से सालभर के बिल एवं भुगतान संबंधी पास बुक को भी देखा जा सकेगा।

एक से 22 अप्रैल तक उर्वरक बिक्री 32 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 10.63 लाख टन

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी लॉकडाऊन लागू होने के बावजूद चालू माह में 22 तारीख तक उर्वरकों की बिक्री 32 प्रतिशत बढ़कर 10.63 लाख टन रही। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि इस बार "उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री" हुई है और कहा कि वह खरीफ की बुवाई के लिए किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। एक सरकारी बयान में कहा गया, "1-22 अप्रैल, 2020 के दौरान, किसानों को 10.63 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 8.02 लाख टन की बिक्री से 32 प्रतिशत अधिक है।" डीलरों ने इस दौरान 15.77 लाख टन उर्वरक खरीदा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में डीलरों की कुल 10.79 लाख टन खरीद की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय स्तर के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर भारी रोक के बावजूद रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के कारण उर्वरक विभाग, देश में उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी बाधा के कर रहा है।" केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा: "उर्वरकों की कोई समस्या नहीं है। राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।" गौड़ा ने कहा कि सरकार किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बंदरगाह कर्मचारियों की कोविड- 19 से मौत पर 50 लाख रुपये का मुआवजा देगी सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मंगलवार को घोषणा की। सरकार ने कहा है कि कोविड- 19 के कारण मृत्यू होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2019 तक के लिये है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुये कहा है, "बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गये और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।" मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध करायेंगे। वक्तव्य में कहा गया है कि इस मामले में संबंधित बंदरगाह का चेयरमैन सक्षम प्राधिकरण होगा। कोविड- 19 से मृत्यू की वैधता जांचने और मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि का दावा करने अथवा उसका वितरण करने के मामले में भी बंदरगाह चेयरमैन ही सक्षम प्राधिकरण होगा। इसमें कहा गया है कि यह मुआवजा केवल कोरोना वायरस के मामले में ही लागू होगा और यह प्रावधान 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगा। देश में -दीनदयाल (पूर्व में कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मुर्मगांव, न्यू मंगलूरू, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पूर्व में एन्नोर), वीओ चिदम्बारनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) -- 12 प्रमुख बंदरगाह हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।